

ईरान, इजराइल और अमेरिका के मध्य चल रहे सैन्य संघर्ष में भारत की भूमिका

डॉ०सतीश चन्द्र जोशी, असिस्टेंट प्रोफेसर सैन्य विज्ञान,

राजकीय महाविद्यालय उफरैखाल (पौड़ी गढ़वाल) उत्तराखंड

सारांश— 2026 में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहे प्रत्यक्ष सैन्य संघर्ष में भारत की भूमिका अत्यंत जटिल है। सैन्य और रणनीतिक दृष्टिकोण से भारत की भूमिका का सिद्धांत आधारित तटस्थता के साथ एक अत्यंत सतर्क संतुलनकारी भूमिका के रूप में देखा जा सकता है। ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को बंद करने और तनाव बढ़ने के बाद, भारतीय नौसेना ने अपने व्यापारिक जहाजों और ऊर्जा आपूर्ति (तेल व गैस) की रक्षा के लिए फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में युद्धपोत तैनात किए हैं। भारतीय नौसेना अपनी समुद्री संपत्ति को नेटवर्क-आधारित, लचीला और एकीकृत बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिसमें स्वायत्त प्रणालियों (drones) का अधिक उपयोग शामिल है। रणनीतिक संतुलन भारत ने ईरान और इजराइल दोनों के साथ राजनयिक संबंध जारी रखते हुए तटस्थता बनाए रखने का प्रयास किया है, ताकि उसके रणनीतिक हित सुरक्षित रहें। रणनीतिक दुविधा और संतुलन, अमेरिका-इजराइल के साथ संबंध भारत ने क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के हमलों की निंदा की है, लेकिन सीधे तौर पर ईरान के खिलाफ कोई आक्रामक रुख नहीं अपनाया। ईरान के साथ संबंध: चाबहार बंदरगाह के माध्यम से कनेक्टिविटी के लिए ईरान महत्वपूर्ण है। भारत ने अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच भी ईरानी तेल पर निर्भरता को कम किया है लेकिन कूटनीतिक रूप से ईरान से दूरी नहीं बनाई है। सुरक्षा प्रदाता के रूप में भारत खुद को हिंद महासागर क्षेत्र में एक शुद्ध सुरक्षा प्रदाता (Net Security Provider) के रूप में स्थापित कर रहा है, जो मानवीय सहायता और खोज व बचाव अभियान (Search and Rescue) में अग्रणी है। संघर्ष के आर्थिक-सैन्य प्रभाव और आयातित मुद्रास्फीति और ऊर्जा सुरक्षा युद्ध के कारण तेल की कीमतें बढ़ने से भारत की अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ा है।

मुख्य शब्द— ड्रोन झुंड, शुद्ध सुरक्षा प्रदाता, स्वायत्त प्रणालियाँ, नागरिक सुरक्षा, मिशन सुदर्शन चक्र।

परिचय— भारत ने तेल के स्रोतों का विविधीकरण किया है और पश्चिम अफ्रीका व अमेरिका से आपूर्ति बढ़ा रहा है। रक्षा तैयारियों में भारत इस संघर्ष का बारीकी से अध्ययन कर रहा है। इसमें स्टैंड-ऑफ हथियार, मजबूत वायु रक्षा प्रणाली, और गोला-बारूद के पर्याप्त भंडार के महत्व को समझा गया है। साइबर और ड्रोन युद्ध यह युद्ध 21वीं सदी के युद्ध का एक प्रयोगशाला है, जिसमें ड्रोन झुंड (Drone Swarms) और साइबर हमलों का उपयोग देखा गया है।

भारत ने रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित रखने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र जैसे कदमों पर विचार किया है। क्षेत्रीय गठबंधन में भारत ब्रिक्स (BRICS) में शामिल रहते हुए भी उन देशों (अमेरिका–इजरायल) के साथ रणनीतिक साझेदारी बनाए हुए है, जो ईरान के खिलाफ हैं, जिसे कई विश्लेषक एक बैलेंसिंग एक्ट के रूप में देखते हैं। नागरिक सुरक्षा मध्य पूर्व में रहने वाले लगभग 9 मिलियन से अधिक भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, भारत ने निकासी की योजना और कूटनीतिक संवाद बनाए रखा है। ईरान–इजराइल–अमेरिका युद्ध (2026) में भारत की भूमिका सैन्य भागीदारी के बजाय रणनीतिक संयम, समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने, और कूटनीतिक–आर्थिक संतुलन पर टिकी हुई है। भारत ने खुद को सीधे संघर्ष में न झोंकते हुए अपने राष्ट्रीय हितों (ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता) को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।

फरवरी 2026 के आखिर में अमेरिका और ईरान के बीच टकराव शुरू हो गया। इसकी वजह थी अमेरिकी और इजराइली सेनाओं का ईरान की परमाणु संरचना पर हमला, जिसके जवाब में तेहरान ने खाड़ी क्षेत्र के बुनियादी ढांचे पर मिसाइल हमला किया। इस घटना ने मध्य पूर्व को अस्थिरता के एक नए दौर में धकेल दिया है। तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, होर्मुज जलडमरूमध्य से होने वाली शिपिंग में बार–बार रुकावटें आ रही हैं, और इस क्षेत्र ने एक बार फिर दुनिया को यह याद दिला दिया है कि वह वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए कितना महत्वपूर्ण है। भारत जिसके इस क्षेत्र में बहुत बड़े हित जुड़े हैं ऊर्जा पर भारी निर्भरता से लेकर बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों की मौजूदगी और बढ़ते कूटनीतिक संबंधों तथा इस तरह की उथल–पुथल उसकी विदेश नीति के लचीलेपन और उसकी एकजुटता की कड़ी परीक्षा लेती है। कई दशकों से, भारत एक ऐसी रणनीति पर चल रहा है जिसे संतुलित बहु–संरक्षण के तौर पर सबसे अच्छी तरह से समझा जा सकता है। किसी कठोर गुट में बंधने के बजाय, नई दिल्ली ने ईरान, खाड़ी देशों के राजतंत्रों, इजराइल और अमेरिका इन सभी के साथ समानांतर संबंध बनाए हैं। कूटनीति के इस संतुलन को बनाए रखना अक्सर मुश्किल बताया जाता रहा है, लेकिन संकट के क्षणों में ही इसकी अंतर्निहित सार्थकता सिद्ध होती है। मौजूदा संघर्ष भी इसका कोई अपवाद नहीं है। भारत की प्रतिक्रिया काफी नपी–तुली और सोच–समझकर दी गई है, उसने सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है, अपने आर्थिक हितों की रक्षा की है, और इस संघर्ष में शामिल हर पक्ष के साथ संवाद के रास्ते खुले रखे हैं। ऐसा करके, नई दिल्ली ने इस क्षेत्र में अपनी रणनीतिक स्वायत्तता और अपने दीर्घकालिक हितों दोनों को सुरक्षित रखने का प्रयास किया है।

इस संकट का आर्थिक तात्कालिक रूप से गंभीर चिंता का विषय है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 88 प्रतिशत कच्चा तेल आयात करता है, और होर्मुज जलडमरूमध्य जिससे होकर दुनिया की ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा प्रवाहित होता है में होने वाली किसी भी रुकावट का असर अनिवार्य रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। टैंकरों की आवाजाही में भारी कमी और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल ने भारत के पहले से ही काफी बड़े ऊर्जा आयात बिल को और बढ़ाने का खतरा पैदा कर दिया था। फिर भी, हाल के वर्षों में सरकार द्वारा ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने

और रणनीतिक भंडार (strategic reserves) बनाने पर दिए गए जोर ने भारत को कुछ हद तक सुरक्षा प्रदान की है। लगभग दो महीने की खपत के बराबर पेट्रोलियम भंडार होने और रूस, अमेरिका तथा अन्य आपूर्तिकर्ताओं से अतिरिक्त आपूर्ति मिलने के कारण, भारत इस तात्कालिक झटके को झेलने में कामयाब रहा है। इसका व्यापक सबक यह है कि ऊर्जा नीति में लचीलापन अब केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि एक आवश्यकता बन गया है विशेषकर ऐसे देश के लिए जिसकी विकास यात्रा काफी हद तक आयातित ईंधन पर निर्भर करती है। भारत अपने कच्चे तेल का लगभग 88 प्रतिशत हिस्सा आयात करता है, और होर्मुज जलडमरूमध्य में किसी भी तरह की रुकावट का असर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। टैंकरों की आवाजाही में भारी कमी और कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से भारत का पहले से ही काफी बड़ा ऊर्जा आयात बिल और बढ़ने का खतरा है।

भारत और ईरान के बीच आर्थिक संबंधों को रचनात्मक तरीके से बनाए रखा गया है। प्रतिबंधों के कारण रुपये में तेल का व्यापार रुक जाने के बावजूद, नई दिल्ली ने रियायती दरों पर ईरानी LPG की खेप के लिए एक मानवीय छूट (humanitarian window) पर बातचीत की, और उर्वरकों की कमी को टालने के लिए 500,000 टन LPG हासिल की। इस रणनीतिक व्यावहारिकता ने भारत को बिना किसी दंड का सामना किए, अपनी कुल ऊर्जा जरूरतों का 5 प्रतिशत हिस्सा ईरान से पूरा करने में सक्षम बनाया है। UAE और सऊदी अरब से बढ़े हुए निवेश ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं में 10 अरब के साथ इन चीजों में संतुलन बनाकर, भारत ने न केवल घरेलू कीमतों को स्थिर किया है, बल्कि खुद को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में भी स्थापित किया है, जिससे लंबे समय तक टिकने वाली मजबूती को बढ़ावा मिला है।

एक और उतनी ही महत्वपूर्ण चिंता खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीय प्रवासियों के कल्याण से जुड़ी है। लगभग 1 करोड़ भारतीय पूरे पश्चिम एशिया में रहते और काम करते हैं, और उनके द्वारा भेजी गई रकम (रेमिटेंस) भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। कोई भी क्षेत्रीय संघर्ष जो हवाई यात्रा, आर्थिक गतिविधियों या बुनियादी ढांचे को बाधित करता है, वह अनिवार्य रूप से इन समुदायों को जोखिम में डाल देता है। बढ़ती शत्रुता के जवाब में, विदेश मंत्रालय ने निकासी योजनाओं और आपातकालीन सहायता के समन्वय के लिए तुरंत कदम उठाए। ऐसे उपाय इस क्षेत्र के साथ भारत के जुड़ाव के मानवीय पहलू को रेखांकित करते हैं। दिल्ली को विदेशों में रहने वाले अपने नागरिकों की सुरक्षा और आजीविका के प्रति भी सचेत रहना चाहिए। इस समीकरण में ईरान के साथ भारत के संबंधों का एक विशेष रूप से संवेदनशील स्थान है। पश्चिमी प्रतिबंधों और भू-राजनीतिक तनावों ने अक्सर तेहरान के साथ जुड़ाव को जटिल बना दिया है, फिर भी भारत ने लगातार ईरान को एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में देखा है ऊर्जा सुरक्षा और मध्य एशिया तथा अफगानिस्तान से जुड़ाव, दोनों ही दृष्टियों से। चाबहार बंदरगाह के विकास जैसी परियोजनाएं इस दीर्घकालिक रणनीतिक तर्क को दर्शाती हैं। मौजूदा संकट के बीच भी, नई दिल्ली ने यह सुनिश्चित करने में सावधानी बरती है कि ईरान के साथ उसका सहयोग पटरी से न उतरे। साथ ही, भारत खाड़ी देशों के अपने भागीदारों

जैसे कि UAE और सऊदी अरब के साथ अपने संबंधों को गहरा करना जारी रखे हुए हैं इन देशों का निवेश और आर्थिक जुड़ाव अब पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। इन समानांतर संबंधों को संभालने के लिए कूटनीतिक कुशलता की आवश्यकता होती है, लेकिन सभी पक्षों के साथ जुड़ने की यही क्षमता भारत को दांव-पेच खेलने (manoeuvre) का अवसर प्रदान करती है।

भारत की मध्य-पूर्व नीति धीरे-धीरे परिपक्व हो रही है। इस क्षेत्र को अब केवल ऊर्जा आयात के चश्मे से नहीं देखा जाता, बल्कि एक ऐसे जटिल रणनीतिक मंच के रूप में देखा जाता है जहाँ आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा हित आपस में मिलते हैं। मौजूदा संकट विविध साझेदारियों और लचीली कूटनीति को बनाए रखने के महत्व को और अधिक पुष्ट करता है।

रणनीतिक दृष्टि से, यह संघर्ष भारत के क्षेत्रीय जुड़ाव को आकार देने में कनेक्टिविटी (संपर्क) पहलों के महत्व को भी उजागर करता है। चाबहार परियोजना जो व्यापक अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे से जुड़ी है मध्य एशिया और उससे आगे के बाजारों तक पहुँचने के भारत के प्रयासों का केंद्र बनी हुई है इसके माध्यम से भारत को केवल पारंपरिक मार्गों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। साथ ही, नए ढांचे जैसे कि खाड़ी देशों और इजराइल के साथ उभरती आर्थिक और सुरक्षा साझेदारियाँ भारत की विकसित होती क्षेत्रीय भूमिका को दर्शाते हैं। नई दिल्ली के सामने चुनौती यह नहीं है कि वह एक धुरी (Pole) को दूसरे पर वरीयता दे, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि ये पहले एक-दूसरे को कमजोर करने के बजाय एक-दूसरे की पूरक बनें।

भारत ने सावधानी पूर्ण तटस्थता का कूटनीतिक रुख अपनाने का प्रयास किया है। नई दिल्ली ने संयम, संवाद और संघर्ष को और अधिक बढ़ने से रोकने की आवश्यकता पर जोर दिया है। इस तरह की स्थिति भारत को सभी पक्षों के साथ जुड़े रहने का मौका देती है, साथ ही किसी एक गुट के साथ जुड़ने की धारणा से भी बचाती है। एक ऐसे क्षेत्र में जहाँ आपसी प्रतिद्वंद्विताएँ गहरी जड़ें जमा चुकी हैं, यह संतुलित रवैया भारत की विश्वसनीयता को एक पक्षपाती खिलाड़ी के बजाय एक जिम्मेदार हितधारक के रूप में बढ़ाता है। इसका व्यापक अर्थ यह है कि भारत की मध्य-पूर्व नीति धीरे-धीरे परिपक्व हो रही है। अब इस क्षेत्र को केवल ऊर्जा आयात के नजरिए से नहीं, बल्कि एक जटिल रणनीतिक मंच के रूप में देखा जाता है, जहाँ आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा हित आपस में मिलते हैं। मौजूदा संकट विविध साझेदारियाँ बनाए रखने और लचीली कूटनीति के महत्व को और मजबूत करता है। बढ़ते भू-राजनीतिक मुकाबले के इस दौर में, भारत जैसे व्यापक हितों वाले देश के लिए कठोर गठबंधन सीमित लाभ ही देते हैं।

अंततः, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता टकराव उस अस्थिरता की एक और याद दिलाता है जो मध्य-पूर्व की पहचान बनी हुई है। भारत के लिए चुनौती ऐसी उथल-पुथल से बचने में नहीं है जो कि असंभव है, बल्कि इसे समझदारी और रणनीतिक स्पष्टता के साथ संभालने में है। नई दिल्ली की अब तक की प्रतिक्रिया इस जागरूकता को दर्शाती है कि आज की दुनिया में प्रभाव अक्सर किसी एक पक्ष को चुनने से नहीं, बल्कि सभी पक्षों के साथ जुड़ने

की क्षमता बनाए रखने से आता है। इस लिहाज से, भारत का सावधानीपूर्वक संतुलित दृष्टिकोण हिचकिचाहट का संकेत कम और रणनीतिक परिपक्वता का दावा ज्यादा है। चुनौतियाँ निश्चित रूप से हैं, लेकिन भारत जैसी उभरती हुई शक्ति के लिए संतुलन केवल अस्तित्व बनाए रखना नहीं है बल्कि यह प्रभाव का मूल तत्व है।

रक्षा-औद्योगिक इकोसिस्टम को निशाना बनाना पश्चिम एशिया में युद्ध और भारत के लिए एक सबक, चल रहे इस युद्ध में, ईरान का रक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका और इजराइल के लिए एक मुख्य निशाना रहा है। इसका मकसद यह पक्का करना है कि युद्ध खत्म होने तक, अमेरिका और इजराइल के हितों को सैन्य रूप से खतरा पहुँचाने की ईरान की क्षमता को जितना हो सके, कम कर दिया जाए। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत के विरोधी देश, भारत के रक्षा उद्योगों को निशाना बनाने के लिए उनका अध्ययन कर रहे हैं और उन पर वॉर-गेमिंग (युद्ध का अभ्यास) कर रहे हैं। भारत के रक्षा-औद्योगिक इकोसिस्टम को सुरक्षित रखने के लिए कई कदम उठाने की जरूरत पड़ सकती है उदाहरण के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट की शुरुआत से ही उसके डिजाइन आर्किटेक्चर में मिशन सुदर्शन चक्र को शामिल करना।

28 फरवरी 2026 को सुबह 9:45 बजे (तेहरान के समय के अनुसार), अमेरिका और इजराइल ने जमीन और समुद्र, दोनों तरफ से 100 से ज्यादा विमानों की खेप के साथ एक बड़ा संयुक्त हमला किया, जिसने एक एकल समन्वित लहर का रूप ले लिया। ऑपरेशन के पहले 57 घंटों में, अमेरिका और इजराइल की संयुक्त सेनाओं ने ईरान के वरिष्ठ राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व, कमांड-एंड-कंट्रोल सिस्टम, नौसैनिक संपत्तियों, बैलिस्टिक मिसाइल सुविधाओं और खुफिया इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए। इन संयुक्त ऑपरेशनों की शुरुआत 'U-S- CYBERCOM U-S- Cyber Command vkSj USSPACECOM U-S- Space Command, द्वारा की गई थी, जिन्होंने नॉन-काइनेटिक (अ-गतिज) प्रभावों की परतें बिछाते हुए, ईरान की देखने, संवाद करने और जवाब देने की क्षमता को बाधित, कमजोर और अंधा कर दिया। दिन के उजाले में किया गया यह संयुक्त हमला, इजराइली रक्षा बलों (IDF) द्वारा शुरू की गई एक ट्रिगर घटना (शुरुआती कार्रवाई) के बाद हुआ था, जिसे अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का समर्थन प्राप्त था।

अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने 6 मार्च को बताया कि 28 फरवरी को अभियान शुरू होने के बाद से, उनकी सेनाओं ने ईरान में 3,000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए हैं और अकेले IDF ने ही पिछले 48 घंटों में 300 ठिकानों को निशाना बनाया है। इस दौरान, इन सेनाओं ने मध्य ईरान तक अपनी हवाई वर्चस्व (air dominance) का विस्तार किया और ईरानी नौसेना को कमजोर कर दिया। ऑपरेशन्स की तीव्रता के बावजूद, युद्ध के अमेरिकी राजनीतिक और सैन्य उद्देश्यों को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, जिन्हें अलग-अलग तरीकों से बताया गया है, जिनमें बदलती हुई और कभी-कभी विरोधाभासी स्थितियाँ भी शामिल हैं। ऑपरेशन्स के उद्देश्यों को लेकर अनिश्चितता के बावजूद, एक बात बिल्कुल साफ है यह कि ईरानी रक्षा उद्योग को निशाना बनाया जायें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि युद्ध के अंत तक, अमेरिका और इजराइल के हितों को सैन्य रूप से खतरा पहुँचाने की ईरान की क्षमता

को अधिकतम कम कर दिया जाए। ईरानी रक्षा औद्योगिक बुनियादी ढांचे को हो रहे नुकसान पर चर्चा करना, यह देखना है कि यह निशाना बनाने की रणनीति युद्ध के बड़े राजनीतिक और सैन्य उद्देश्यों में कैसे फिट बैठती है, और भारत के लिए इससे क्या सबक सीखे जा सकते हैं।

युद्ध के राजनीतिक और सैन्य उद्देश्य: ईरान की परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल क्षमताओं के बारे में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध खुफिया जानकारी, या इस विषय से जुड़ी बहसों और विवादों में जाए बिना, यहाँ युद्ध के उन उद्देश्यों को सूचीबद्ध करने का प्रयास किया गया है, जो मीडिया रिपोर्टों, प्रेस ब्रीफ और अमेरिका तथा इजराइल के सरकारी प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए बयानों से संबंधित हैं।

युद्ध के राजनीतिक उद्देश्य: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इस युद्ध को अमेरिका और ईरान के बीच 47 साल पुराने शत्रुतापूर्ण संबंधों की परिणति के रूप में पेश किया है, जिसकी शुरुआत 1979 में हुई थी उनका तर्क है कि इस्लामिक गणराज्य ने लगातार अमेरिका के हितों को नुकसान पहुँचाया है और इस क्षेत्र को अस्थिर किया है। हमलों के लिए उनके द्वारा दी गई कथित दलीलों में ईरान का कथित परमाणु हथियार कार्यक्रम और उसके चल रहे अंतरिक्ष कार्यक्रम से विकसित हो रही अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता शामिल है। 2 मार्च 2026 को पेंटागन की प्रेस ब्रीफिंग में, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के मुख्य उद्देश्य ईरानी सैन्य क्षमताओं को कम करने पर केंद्रित थे, विशेष रूप से मिसाइल जखीरे से संबंधित क्षमताओं को और इसके विस्तार के तौर पर ईरान की अपनी सीमाओं के बाहर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने की क्षमता को कम करना था। उन अन्य क्षमताओं में से एक, जो ईरान को अपनी सीमाओं के बाहर शक्ति का प्रदर्शन करने में सक्षम बनाती है, गैर-सरकारी तत्वों (non-state actors) और मिलिशिया बलों का एक नेटवर्क है, जिसे ईरान ने पिछले कई वर्षों में बनाया और पोषित किया है इसमें हमास और हिज्बुल्लाह जैसे संगठन शामिल हैं। हमास और हिज्बुल्लाह की सैन्य क्षमताएँ भले ही हाल ही में गाजा युद्ध के दौरान इजराइल द्वारा काफी हद तक कमजोर की जा चुकी है, व पुर्नगठितकी जा सकती है, इसमें कोई सन्देह नहीं और इसी से यह बहाल की जा सकती हैं।

ईरान में सत्ता परिवर्तन एक और राजनीतिक उद्देश्य है जिसे राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिकी प्रशासन के अन्य अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से जाहिर किया है। ट्रंप ने ईरानियों से आग्रह किया है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएँ और अपनी सरकार की बागडोर अपने हाथों में ले लें। राष्ट्रपति ट्रंप ने परमाणु अप्रसार के मुद्दे को भी सत्ता परिवर्तन से जोड़ा है। 28 फरवरी को हमलों की शुरुआत के बाद अपनी टिप्पणियों में, उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि इन हमलों का एक मुख्य उद्देश्य सत्ता परिवर्तन के माध्यम से परमाणु अप्रसार की है।

अमेरिका के विपरीत, जो चल रहे इस युद्ध को पिछले 47 वर्षों में ईरान की शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों का परिणाम मानता है, इजराइल इस युद्ध को 7 अक्टूबर 2023 की घटनाओं के बाद पश्चिम एशिया को फिर से व्यवस्थित करने के एक अवसर के रूप में देखता है। इजराइल उन सभी सैन्य ताकतों को हराना और नष्ट करना चाहता है जो उसे

चुनौती देने में सक्षम हैं, जिसमें ईरान भी शामिल है। इजराइल अमेरिका द्वारा जाहिर किए गए सभी राजनीतिक उद्देश्यों का समर्थन करता है, लेकिन अमेरिका और इजराइल के हितों के बीच कुछ ऐसे मुद्दे भी हैं जिन पर दोनों के विचार अलग-अलग हैं। अमेरिका के इस क्षेत्र के देशों के साथ व्यापक राजनीतिक, कूटनीतिक और आर्थिक संबंध हैं। यदि यह युद्ध लंबा खिंचता है, तो इससे इस क्षेत्र में अमेरिका के हितों को नुकसान पहुँच सकता है और वैश्विक अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है। राष्ट्रपति ट्रंप इस बात से भी बंधे हुए हैं कि वे जमीन पर अपनी सेना (boots on the ground) तैनात करना न करें, जो उनकी कभी न खत्म होने वाले युद्धों (forever wars) से बचने की नीति के अनुरूप है। दूसरी ओर, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस युद्ध को अपनी घरेलू राजनीतिक चुनौतियों से पार पाने के एक अवसर के रूप में देख सकते हैं। उनके हित में यही होगा कि वे इस युद्ध को लंबा खींचें, जिससे उन्हें उन इजराइली नागरिकों का समर्थन मिलता रहेगा जिन्होंने युद्धकाल में उनके नेतृत्व पर अपना भरोसा जताया है।

इस युद्ध के सैन्य उद्देश्य

राजनीतिक उद्देश्य किसी युद्ध के व्यापक लक्ष्यों को परिभाषित करते हैं, जबकि सैन्य उद्देश्य विशिष्ट और प्राप्त किए जा सकने वाले ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें इन लक्ष्यों को पूरा करने में सहायता देने के लिए तैयार किया जाता है। 2 मार्च 2026 को अपनी प्रेस ब्रीफिंग में, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने पत्रकारों से कहा कि अमेरिकी सेना का मकसद अमेरिका की रक्षा और बचाव करना है, और क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर, ईरान को अपनी सीमाओं के बाहर अपनी ताकत दिखाने की क्षमता हासिल करने से रोकना और जरूरत के हिसाब से आगे की कार्रवाई के लिए तैयार रहना है। पेंटागन के मुख्य प्रवक्ता शॉन पार्नेल ने सैन्य उद्देश्यों की सूची दी है, वे हैं ईरान की परमाणु मिसाइल क्षमता को नष्ट करना, उसकी नौसेना को खत्म करना, ईरान समर्थित आतंकियों को गुर्गों को दुनिया को अस्थिर करने से रोकना, और शासन को सड़क किनारे बम लगाने से रोकना। सैन्य उद्देश्यों के समर्थन में, अमेरिका और इजराइल की संयुक्त सेना ने परमाणु सुविधाओं, बैलिस्टिक मिसाइल बुनियादी ढांचे और रडार प्रतिष्ठानों, साथ ही नेतृत्व के ठिकानों और ईरान की सैन्य कमान संरचना के तत्वों पर विशेष हमले किए हैं। US CENTCOM की लक्ष्य सूची में शामिल हैं इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड कॉर्पस (IRGC) की कमान और नियंत्रण सुविधाएं, हवाई रक्षा क्षमताएं, मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइटें, और सैन्य हवाई अड्डे।

संयुक्त सेनाओं की अभियान योजना और रक्षा उद्योग को निशाना बनाना

ईरान के खिलाफ अमेरिका & IDF के ऑपरेशन, जो 28 फरवरी को शुरू हुए थे, एक एहतियाती, कई चरणों वाले हवाई अभियान के तौर पर शुरू हुए थे, ताकि इस ब्रीफ में कहीं और बताए गए राजनीतिक और सैन्य उद्देश्यों को हासिल किया जा सके। अभियान योजना दो स्तंभों पर टिकी है, जिसमें संसाधनों का आवंटन एक गतिशील दृष्टिकोण के अनुसार होता है, जो ऑपरेशन की प्रगति और ईरान की प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। पहला स्तंभ ईरान की

हवाई सुरक्षा को दबाना, उसकी कमान और नियंत्रण को खत्म करना, और बैलिस्टिक मिसाइलों, ड्रोन और नौसैनिक संपत्तियों के साथ जवाबी कार्रवाई करने की उसकी क्षमता को सीमित करना सुनिश्चित करता है। सेनाओं ने ईरान की परमाणु सुविधाओं को भी निशाना बनाया है, साथ ही ईरान द्वारा बनाए और समर्थित मिलिशिया और गैर-सरकारी तत्वों को भी। दूसरा स्तंभ ईरान की रक्षा औद्योगिक संपत्तियों, विशेष रूप से मिसाइल और ड्रोन उत्पादन सुविधाओं को निशाना बनाकर ईरान की सैन्य क्षमता को लंबे समय तक कमजोर करना सुनिश्चित करता है।

ईरान की हवाई सुरक्षा को दबाना, संयुक्त सेनाओं के दृष्टिकोण से, ईरान की हवाई सुरक्षा को दबाना, निर्धारित क्षेत्रों पश्चिमी ईरान, तेहरान के ऊपर, और बाद में पूर्वी ईरान तक विस्तार करते हुए हवाई श्रेष्ठता हासिल करने के लिए जरूरी है। इसमें ईरान की हवाई रक्षा प्रणालियों और मिसाइल लॉन्चरों को नष्ट करना शामिल है। ईरान की जवाबी क्षमता को कमजोर करना पश्चिमी ताकतों के नजरिए से यह जरूरी है कि ईरान की जवाबी क्षमता को कमजोर और नष्ट कर दिया जाए। संयुक्त सेनाएं अपने हवाई अभियान के पहले दिन से ही ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चरों और मिसाइल ठिकानों को निशाना बना रही हैं, जिनमें संभवतः मिसाइल के जखीरे भी शामिल हैं। ये सेनाएं ईरान की नौसेना संपत्तियों को भी निशाना बना रही हैं, ताकि उन्हें अंतरराष्ट्रीय जहाजरानी में बाधा डालने और अमेरिका व इजरायल की नौसेना संपत्तियों पर हमला करने से रोका जा सके।

ईरान के कमांड-एंड-कंट्रोल में बाधा डालना अभियान की शुरुआत से ही, संयुक्त सेनाओं ने ईरान के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व के खिलाफ डीकैपिटेशन स्ट्राइक (शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाने वाले हमले) किए हैं। सेनाएं नेतृत्व के अतीत, वर्तमान और भविष्य को निशाना बना रही हैं, ताकि कमांड-एंड-कंट्रोल में बाधा डाली जा सके और सत्ता परिवर्तन के बड़े लक्ष्य को हासिल किया जा सके।

ईरान के रक्षा औद्योगिक आधार को निशाना बनाना, ईरान के रक्षा उद्योग को कमजोर करने से अमेरिका और इजरायल के रणनीतिक लक्ष्यों को बढ़ावा मिलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इससे ईरान की अपनी शक्ति दिखाने की क्षमता कमजोर होती है, और ऐसी स्थितियाँ बनती हैं जो वहाँ की सरकार (शासन) को अस्थिर करती हैं। ईरान के रक्षा उद्योग को नष्ट करने से अमेरिका और इजरायल के राजनीतिक और सैन्य लक्ष्यों को सीधे तौर पर मदद मिलती है। इससे ईरान की लंबे समय तक अपनी शक्ति दिखाने की क्षमता पंगु हो जाती है, और ऐसी स्थितियाँ बनती हैं जो वहाँ की सरकार को अस्थिर करती हैं।

राजनीतिक लक्ष्यों के साथ तालमेल, देश की औद्योगिक रीढ़ को कमजोर करने से सीधे तौर पर प्लॉट की युद्ध की तैयारी कमजोर होती है। साथ ही, इससे सरकार की वैधता और आर्थिक मजबूती भी कम होती है, जिससे सरकार बदलने का दबाव बढ़ जाता है।

सैन्य लक्ष्यों के साथ तालमेल: संयुक्त सेना ने ईरान के रक्षा औद्योगिक परिसर को प्राथमिकता पर निशाना बनाया। इसका मकसद उत्पादन और नई खोजों की प्रक्रिया को बाधित करके, ईरान की लंबे समय तक युद्ध लड़ने की क्षमता

को रोकना था। इन ठिकानों को निशाना बनाने से ईरान उन मिसाइलों, रॉकेटों और गोला-बारूद की भरपाई नहीं कर पाता जो युद्ध में खर्च हो चुके हैं, और उसे अपने सीमित भंडार पर निर्भर रहना पड़ता है। रक्षा उद्योगों को निशाना बनाने से अमेरिका और इजराइल की सेनाओं, बुनियादी ढाँचे और अन्य हितों को नुकसान पहुँचाने की ईरान की जवाबी क्षमता भी कम हो जाती है। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने 10 मार्च को पेंटागन में हुई एक ब्रीफिंग के दौरान कहा, युद्ध शुरू होने के बाद से पिछले 24 घंटों में ईरान ने सबसे कम संख्या में मिसाइलें दागी हैं। मिसाइल दागने की घटनाओं में आई यह कमी हवाई अभियान की सफलता और ईरान की औद्योगिक उत्पादन क्षमता में आई गिरावट का संकेत है। यह भी संभव है कि ईरान किसी लंबे युद्ध के लिए अपने सीमित भंडार को बचाकर रख रहा हो। फिर भी, उसके रक्षा उद्योगों के कमजोर होने का ईरान की युद्ध लड़ने की क्षमता पर लंबे समय तक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। फॉक्स न्यूज से बात करते हुए एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि इस अभियान के पहले 12 घंटों में संयुक्त सेना ने लगभग 900 हमले किए। हालाँकि, सबसे दिलचस्प बात यह देखना है कि दोनों सेनाओं के बीच जिम्मेदारियों का बँटवारा किस तरह किया गया था। अमेरिकी सेना ने ईरान के मिसाइल लॉन्चरों और मिसाइल कार्यक्रम पर ध्यान केंद्रित किया जबकि इजराइली हमलों ने ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों और मिसाइल कार्यक्रम को निशाना बनाया। अमेरिका और इजराइल, दोनों द्वारा ईरान के मिसाइल कार्यक्रम को निशाना बनाना इस बात का संकेत है कि वे ईरान के रक्षा उद्योग को नष्ट करने के काम को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं।

अमेरिका और इजराइल की संयुक्त सेना ने ईरान के विश्वविद्यालयों, अनुसंधान और विकास केंद्रों, विनिर्माण इकाइयों और परीक्षण सुविधाओं को निशाना बनाया है। संक्षेप में कहें तो, अमेरिका और इजराइल ईरान के रक्षा-औद्योगिक तंत्र को नष्ट कर रहे हैं। युद्ध के पहले दिन से ही ईरान के रक्षा-औद्योगिक परिसर पर हमले शुरू हो गए थे। हालाँकि, शुरुआती दिनों में, अभियानों का मुख्य उद्देश्य ईरान की वायु रक्षा प्रणाली को दबाना, उसके कमांड और कंट्रोल (नेतृत्व) को खत्म करना, और बैलिस्टिक मिसाइलों तथा ड्रोन से जवाबी हमला करने की उसकी क्षमता को सीमित करना था। तेहरान और पश्चिमी ईरान पर हवाई वर्चस्व हासिल करने के बाद, और फिर धीरे-धीरे देश के पूर्वी हिस्से की ओर विस्तार करते हुए, संयुक्त सेनाओं ने ईरान की रक्षा-औद्योगिक संपत्तियों विशेष रूप से मिसाइल उत्पादन सुविधाओं को निशाना बनाने की कार्रवाई तेज कर दी। इस पहलू पर 5 मार्च 2026 को हुई प्रेस ब्रीफिंग में US CENTCOM के कमांडर एडमिरल ब्रैंड कूपर और अमेरिकी सेनाओं के रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने जोर दिया था। इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एयाल जमीर ने भी इसी बात को दोहराया उन्होंने घोषणा की कि इजराइल इस अभियान के अगले चरण में प्रवेश कर रहा है, जिसमें ईरान की अन्य अनिर्दिष्ट सैन्य क्षमताओं और ईरान के शासन की नींव, को निशाना बनाया जाएगा जिसका सीधा अर्थ ईरान के रक्षा उद्योगों से है।

भारत के लिए सबक: भारत के रक्षा उद्योग मुख्य रूप से बेंगलुरु, हैदराबाद, नासिक, और उत्तर प्रदेश तथा तमिलनाडु में बन रहे दो नए रक्षा-औद्योगिक गलियारों (कॉरिडोर) के साथ-साथ तटीय बंदरगाहों पर केंद्रित हैं। इन उद्योगों

को, अनुसंधान प्रयोगशालाओं, परीक्षण सुविधाओं और इसी तरह की अन्य संस्थाओं के साथ, भविष्य के किसी भी युद्ध में विरोधी पक्ष द्वारा पूरी संभावना है कि प्राथमिकता वाले लक्ष्यों के रूप में चिह्नित किया जाएगा। चल रहे इस युद्ध ने रक्षा-औद्योगिक तंत्र की कमजोरियों को उजागर कर दिया है, और यह स्पष्ट कर दिया है कि युद्धों तथा संघर्षों के दौरान एक सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करने के लिए इन उद्योगों को आवश्यक सुरक्षा प्रदान करना कितना जरूरी है।

रक्षा कंपनियाँ और अन्य सहायक इकाइयाँ, स्वाभाविक रूप से, अपने परिसरों के स्थान का चयन करते समय और उनकी रूपरेखा तैयार करते समय आर्थिक, औद्योगिक और शायद राजनीतिक पहलुओं को प्राथमिकता देती है। इन पहलुओं के साथ-साथ सुरक्षा संबंधी विभिन्न पहलुओं को भी अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए, ताकि बुनियादी ढाँचे की आवश्यक सुरक्षा, कर्मचारियों की सुरक्षा, और एक ऐसे वातावरण को सुनिश्चित किया जा सके जो युद्ध के समय भी उत्पादन श्रृंखला के निर्बाध संचालन को संभव बना सके। इस सन्दर्भ में सरकार के उच्चतम स्तर पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता होगी। रक्षा मंत्रालय के भीतर एक नोडल एजेंसी का गठन किया जा सकता है, जो कानूनों और दिशा-निर्देशों की योजना बनाने तथा उन्हें तैयार करने, और साथ ही (रक्षा) औद्योगिक नीतियों को लागू करने के लिए उत्तरदायी हो। इस संबंध में जिन कुछ मुद्दों पर विचार-विमर्श की आवश्यकता है, वे इस प्रकार हैं।

वायु रक्षा- 15 अगस्त 2025 को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा की, जिसे भारत की ढाल और तलवार कहा गया है और जिसे 2035 तक हासिल किया जाना है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा, वायु रक्षा और हवाई हमले की क्षमताएं प्रदान करना है, जो एक एकीकृत रणनीति का उपयोग करके उन्नत, जटिल, बड़े पैमाने पर और मिश्रित हवाई खतरों का मुकाबला कर सकें। भारत के रक्षा औद्योगिक इकोसिस्टम की सुरक्षा को प्रोजेक्ट की शुरुआत से ही मिशन सुदर्शन चक्र के डिजाइन आर्किटेक्चर में शामिल किया जाना चाहिए। इन नोड्स की सक्रिय रक्षा, रक्षा उद्योगों की सुरक्षा में सबसे महत्वपूर्ण कारक होगी। सक्रिय रक्षा में एक नेटवर्क-आधारित, बहु-स्तरीय प्रणाली शामिल होगी, जो सेंसर, इंटरसेप्टर और कमांड नोड्स को एकीकृत करके ड्रोन, मिसाइलों और विमानों जैसे हवाई खतरों का पता लगाएगी, उन्हें ट्रैक करेगी और उनके टकराने से पहले ही उन्हें बेअसर कर देगी। स्टैंडऑफ स्ट्राइक ऑपरेशंस के अलावा, स्पाइडर्स वेब और राइजिंग लायन जैसे ऑपरेशंस ने स्थिर लक्ष्यों की उन कमजोरियों को उजागर किया है, जिनका फायदा विशेष बल और गैर-सरकारी तत्व (non-state actors) लक्ष्यों के करीब से लॉन्च किए गए मानवरहित प्रणालियों के माध्यम से उठा सकते हैं। उद्योगों को अपने कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली तोड़फोड़ को रोकने के लिए भी पहले से ही एहतियाती कदम उठाने होंगे, क्योंकि विरोधी ताकतें इन कर्मचारियों को अपने पक्ष में कर सकती हैं।

रक्षा उद्योग— विनिर्माण और सहायक ढाँचा स्थापित करते समय रक्षा उद्योग जिन कुछ मुद्दों पर विचार कर सकता है, उनका विवरण नीचे दिया गया है। ये सिफारिशें सामान्य प्रकृति की हैं, और उद्योग के लिए यह उचित होगा कि वह ऐसी पेशेवर परामर्श फर्मों की सेवाएं ले, जिनका सैन्य सुरक्षा मुद्दों को समझने का एक सुसंगत ट्रैक रिकॉर्ड हो और जिनके कार्यक्षेत्र में औद्योगिक इंजीनियरिंग और प्रबंधन भी शामिल हों। उद्योग को अपने लेआउट, कार्यप्रवाह और बुनियादी ढांचे की योजना बनाते समय सैन्य सुरक्षा मुद्दों और व्यावसायिक कार्य प्रणालियों के बीच संतुलन बनाना होगा। चल रहे युद्ध ने इस बात को उजागर किया है कि औद्योगिक इंजीनियरिंग (जो सुविधाओं के लेआउट, सामग्री के प्रवाह और दक्षता से संबंधित है) और औद्योगिक प्रबंधन (जो निर्माण, संसाधनों के आवंटन और विनिर्माण हब के विस्तार की देखरेख करता है) की योजना अलग-थलग रहकर नहीं बनाई जा सकती। रक्षा उद्योगों की स्थापना के स्थान का चयन करते समय सैन्य सुरक्षा एक अनिवार्य कारक के रूप में कार्य करेगी।

औद्योगिक परिसरों का फैलाव और सुदृढ़ीकरण— हाल के युद्धों ने उत्पादन केंद्रों को फैलाने और उन्हें मजबूत बनाने की जरूरत को और बढ़ा दिया है। रक्षा मंत्रालय के भीतर एक नोडल एजेंसी की जरूरत है जो अलग-अलग केंद्रों पर उत्पादन सुविधाओं के फैलाव और सुदृढ़ीकरण के बारे में दिशा-निर्देश जारी करे। एक जैसे उत्पाद बनाने वाले उद्योगों को अलग-अलग केंद्रों पर स्थापित करना होगा। हर केंद्र के भीतर, उत्पादन इकाइयाँ इतनी फैली हुई होनी चाहिए कि वे किसी एक हमले में नष्ट न हो जाएँ। ज्वलनशील पदार्थों को संभालने वाली उत्पादन इकाइयों को अतिरिक्त सावधानियों और सुरक्षा उपायों की जरूरत होगी।

उत्पादन इकाइयों को निष्क्रिय संरचनात्मक सुदृढ़ीकरण का उपयोग करके मजबूत बनाया जा सकता है, ताकि उत्पादन लाइनों, कच्चे माल, तैयार उत्पादों और कर्मचारियों को सुरक्षा मिल सके, और इस तरह युद्ध के समय आपूर्ति बिना किसी रुकावट के जारी रहे। कंपनियाँ श्रेणीबद्ध सुदृढ़ीकरण पर विचार कर सकती हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को स्टील-प्रबलित कंक्रीट के गुंबदों से सुरक्षित किया जाता है, जो 500 किलोग्राम या उससे अधिक वजन वाले बमों का सामना करने में सक्षम हों। परिधि के चारों ओर धमाका-रोधी दीवारें और वेंट तथा छतों के ऊपर ड्रोन-रोधी जाल कुछ अन्य उपाय हैं जिन पर विचार किया जा सकता है। जालों, नकली छतों और नकली इमारतों का उपयोग करके छद्मावरण (कैमोफ्लेज) करने से दुश्मन के लिए निशाने का चयन मुश्किल हो सकता है। कर्मचारियों के लिए भूमिगत बंकरों पर विचार किया जा सकता है। कुशल कर्मचारी किसी भी उद्योग की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति होते हैं और युद्ध के समय उनकी जगह लेना लगभग असंभव होता है। कुछ संवेदनशील और महत्वपूर्ण वस्तुओं के लिए ऐसे बंकरों की भी जरूरत पड़ सकती है जो परमाणु, जैविक और रासायनिक निस्पंदन प्रणालियों से सुसज्जित हों। इसके अलावा, युद्धों के दौरान क्षतिग्रस्त संरचनाओं के पुनर्निर्माण की भी जरूरत होगी, जिसके लिए बिजली उत्पादन और अन्य आवश्यक सुविधाओं से युक्त मॉड्यूलर प्रीफैब्रिकेटेड खंडों की व्यवस्था शुरू से ही की जानी चाहिए। जो कंपनियाँ आयात-निर्भर महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भर हैं, उन्हें सुरक्षित आश्रयों में भंडार जमा करने पर विचार करना

चाहिए, जिनमें स्वचालित कन्वेयर सुरंगें हों और जो उनकी उत्पादन लाइन के डिजाइन से जुड़े हों। तैयार उत्पादों को इन स्थानों से जितनी जल्दी हो सके, हटाना होगा। सरकार को इन रक्षा गलियारों में एक बहु-माध्यम परिवहन प्रणाली की योजना बनानी चाहिए, और ऐसे केंद्र बनाने चाहिए जहाँ रेल लिंक, हवाई पट्टियाँ और हेलीपैड हों, ताकि सामानों का तेजी से वितरण सुनिश्चित किया जा सके।

निष्कर्ष— भारत के रक्षा उद्योगों का अध्ययन किया जा रहा है और भारत के दुश्मन उन्हें अपने संभावित लक्ष्यों के रूप में वॉर-गेम (युद्ध-अभ्यास) में शामिल कर रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फ्लोरिडा के टैम्पा में एक औपचारिक रात्रिभोज में दिए गए भाषण में इस बात का संकेत दिया था। उन्होंने भारत के साथ भविष्य में होने वाले किसी भी सैन्य संघर्ष की स्थिति में गुजरात के जामनगर में स्थित रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की रिफाइनरी को निशाना बनाने की धमकी दी थी। इस तरह, उन्होंने पहली बार भारत की आर्थिक संपत्तियों पर हमला करने के अपने इरादे को जाहिर किया था। ऊपर बताए गए उपायों को कंपनियाँ शायद बहुत खर्चीला, फिजूलखर्ची वाला और यहाँ तक कि बेकार भी मान सकती हैं, क्योंकि कंपनियों के प्रदर्शन का आकलन उनकी बैलेंस शीट के आधार पर किया जाता है। लेकिन, रक्षा उद्योग कोई साधारण उद्योग नहीं होते। किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा उसके रक्षा उद्योगों की सुरक्षा से ही जुड़ी होती है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- एशले रोके, "केन अमेरिका का मकसद ईरान को अपनी सीमाओं से बाहर अपनी ताकत दिखाने से रोकना है", ब्रेकिंग डिफेंस, 2 मार्च 2026।
- जोसेफ ट्रेविथिक, थॉमस न्यूडिक और हॉवर्ड ऑल्टमैन, "ईरान के साथ युद्ध अब अपने तीसरे दिन में", TWZ 2 मार्च 2026।
- एशले रोके, "केन अमेरिका का मकसद ईरान को अपनी सीमाओं से बाहर अपनी ताकत दिखाने से रोकना है, la- 2।
- "ईरान अपडेट शाम की विशेष रिपोर्ट, 7 मार्च 2026", इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर (ISW), 7 मार्च 2026।
- आबिद हुसैन, "जैसे-जैसे अमेरिका-इजरायल युद्ध बढ़ता जा रहा है, ईरान में ट्रंप का अंतिम लक्ष्य क्या है?", अल जजीरा, 9 मार्च 2026।
- सनम वकील और अन्य, "अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमला किया, शासन परिवर्तन की मांग की। तेहरान ने जवाबी हमले किएरु चौथम हाउस के विशेषज्ञों का प्रारंभिक विश्लेषण", चौथम हाउस, 1 मार्च 2026।

- जोसेफ ट्रेविथिक, थॉमस न्यूडिक और हॉवर्ड ऑल्टमैन, "ईरान के साथ युद्ध अब अपने तीसरे दिन में", la- 3.
- इमानुएल फैबियन और जैकब मैगिड, "अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बड़ा संयुक्त हमला किया ट्रंप ने संकेत दिया कि लक्ष्य वहां की सत्ता को पलटना है", द टाइम्स ऑफ इजराइल, 28 फरवरी 2026.
- दार्या डोलजिकोवा और मैथ्यू सैविल, "ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले सैन्य और परमाणु प्रसार का विश्लेषण", RUSI 28 फरवरी 2026.
- आबिद हुसैन, "जैसे-जैसे अमेरिका-इजराइल युद्ध तेज हो रहा है, ईरान को लेकर ट्रंप का अंतिम लक्ष्य क्या है?", अल जजीरा, 9 मार्च 2026.
- ओरी गोल्डबर्ग, "ईरान के मामले में अमेरिका और इजराइल के हित जल्द ही अलग हो सकते हैं", अल जजीरा, 2 मार्च 2026.
- इजराइली अन्य प्रधानमंत्री उम्मीदवारों के मुकाबले नेतन्याहू को ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन उनकी मंशा पर भरोसा नहीं करते। देखें "एक सर्वेक्षण के अनुसार, एक तिहाई से भी कम इजराइली मानते हैं कि देश ने गाजा में हमास के खिलाफ युद्ध जीता है", द टाइम्स ऑफ इजराइल, 30 जनवरी 2026.
- जैसा कि जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में कहा। देखें एशले रोके, "केनरू अमेरिका का उद्देश्य ईरान को अपनी सीमाओं के बाहर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने से रोकना है", la- 2.